मेटा अधिकारी ने की वैष्णव से मुलाकात

- अब व्हाट्सएप भी जांच के दायरे में
- मेटा के अधिकारी अभी कुछ दिनों तक भारत में रहेंगे
- तीन से चार और बैठकें होने की संभावना
- मेटा पहले तकनीकी त्रुटि मानते हुए खेद जता चुका है.

नई दिल्ली, 06 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट अस्थायी रूप से हटाए जाने के विवाद के बाद केंद्र सरकार और मेटा के बीच भारतीय कानूनों के पालन को लेकर बातचीत लगातार जारी है. सूत्रों के के अनुसार मेटा के अधिकारियों से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मुलाकात की है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा की वैश्विक टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रहेगी और इस दौरान तीन से चार और उच्चस्तरीय बैठकें होने की संभावना है. इन बैठकों में फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ-साथ अब व्हाट्सएप के तकनीकी, कानूनी और नियामकीय पहलुओं की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में संचालित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों और अन्य संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि भारत में किसी भी विदेशी कंपनी का संचालन भारतीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और किसी अन्य देश के कानूनी ढांचे के आधार पर यहां सेवाओं का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा. बताया गया है कि आगामी बैठकों में व्हाट्सएप की तकनीकी कार्यप्रणाली, सिस्टम लॉग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी. मेटा पहले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी कर चुका है, लेकिन सरकार उपलब्ध तथ्यों और तकनीकी सूचनाओं का विस्तृत परीक्षण करना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार की चूक या प्रणालीगत कमी की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके.

> सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की बातचीत केवल मेटा तक सीमित नहीं है. एक्स (पूर्व ट्विटर), टेलीग्राम और अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी समय-समय पर संवाद होता रहता है. सरकार का मानना है कि सभी डिजिटल कंपनियों की समाज और कानून के प्रति समान जिम्मेदारी है तथा प्रत्येक प्लेटफॉर्म को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए.

अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत

झांसी, 06 अगस्त. कुख्यात माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम गुरुवार को झांसी में सामने आया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मिलने जा रहे अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने करते हुए बताया कि पूंछ क्षेत्र के ग्राम खिल्ली में हुए सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे की भी मौत हुई है. साथ में उसके एक दोस्त सोनू की भी जान चली गई. तीनों घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

आपने मेरा एकाउंट क्यों किया बैन?

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 06 अगस्त. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेटा और मेटा इंडिया पर आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है.

केजरीवाल ने एक्स पर मेटा और मेटा इंडिया को टैग करते हुए इस संबंध में एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, 'आपने मेरा अकाउंट क्यों प्रतिबंधित कर दिया है? आपके भारत कार्यालय में मौखिक पूछताछ से पता चला कि मेरा अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है. क्यों? आपके कार्यालय में कोई भी कोई कारण नहीं बता रहा है. कोई यह भी नहीं बता रहा कि प्रतिबंध कैसे हटाए जा सकते हैं. लिखे गए सभी ईमेल पर नियमित नोटिफिकेशन के अलावा कोई जवाब नहीं मिला. यह बहुत खराब सेवा है. हमारे प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुको. वरना वह आपको भारत में सिर्फ अपना ही अकाउंट चलाने की इजाजत देंगे.

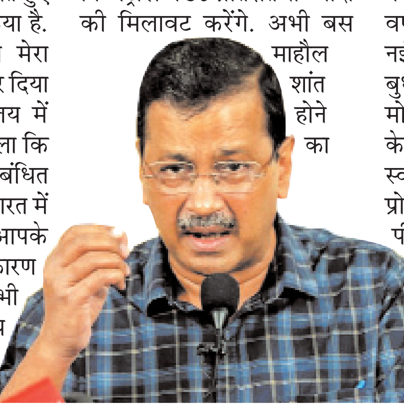

केजरीवाल ने इससे पहले एक पोस्ट में लिखा था, 'मोदी सरकार का क्या प्लान है, पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50 प्रतिशत से ज्यादा की मिलावट करेंगे. अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं. पहले आपकी ई0 और ई10 गाड़ियों में जबरदस्ती ई20 पेट्रोल डालकर कबाड़ा किया. आज अगर आप ई20 नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें जबरदस्ती ई50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी. सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने वाली है. इसलिए अभी कुछ वर्ष आप पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचें. मेटा ने बुधवार को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को पाबंद करने के लिए माफी मांगी थी. उसने यह स्वीकार किया था कि बड़े स्तर प्रोमोशनल एक्टिविटीज के कारण पीएम मोदी का वीडियो भारत के बंद हो गया था. वीडियो को अचानक ही बंद कर देने के कारण केंद्र सरकार ने मेटा से गहरी आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा था.

एक नजर में

दीपके के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता

नई दिल्ली. कॉकरोच जनता पार्टी में आंतरिक बगावत की स्थिति पैदा हो गई है, जहां पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अभिजीत दीपके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली के जंतर-मंतर आंदोलन में शामिल रहे दो युवकों ने बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हो रही सीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय संगठनात्मक बैठक के दौरान यह विवाद खुलकर सामने आया. दीपके के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बैठे दोनों युवकों का आरोप है कि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें संगठन की बैठक में नहीं बुलाया गया और न ही संगठन में कोई जिम्मेदारी दी गई. इस दौरान उन्होंने संगठन से पारदर्शिता बरतने और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की. अभिजीत दीपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवकों का कहना है कि जंतर-मंतर आंदोलन में योगदान देने वाले कई कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है.

पीटीआई की इस्लामाबाद मार्च डेडलाइन तय

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. इमरान खान की जेल में तीन साल की कैद पूरी होने के बीच उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने पार्टी की मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो 27 सितंबर को पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद की ओर मार्च करेंगे. पेशावर में आयोजित पार्टी की बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सोहैल अफरीदी ने कहा कि पीटीआई की पहली मांग इमरान खान और उनकी पत्नी से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर है. उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई तय समय पर होनी चाहिए और अदालतों को मेरिट के आधार पर फैसला करना चाहिए. पार्टी का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं. पीटीआई की दूसरी प्रमुख मांग जेल में इमरान खान से मुलाकातों को लेकर है. पार्टी चाहती है कि उनके वकीलों, डॉक्टरों, रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं को उनसे मुलाकात की अनुमति दोबारा दी जाए. पार्टी नेताओं का आरोप है कि मुलाकातों पर लगी पाबंदियों के कारण इमरान खान तक कानूनी और राजनीतिक जानकारी पहुंचने में बाधा पैदा हो रही है. अफरीदी ने सभा के दौरान सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो पार्टी 27 सितंबर को इस्लामाबाद की ओर कूच करेगी. उन्होंने समर्थकों से आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील भी की. उन्होंने यह भी दावा किया कि पीटीआई के पास इतनी ताकत है कि वह 30 मिनट में इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकती है.

पीएम और गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें

संसद को बाधित करने के लिए सत्तापक्ष जिम्मेदार : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली, 6 अगस्त. कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में गतिरोध के लिए सत्तापक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में सदन में आकर जवाब देंगे तब ही संसद सुचारु रूप से चल सकेगी.

श्री खरगे ने गुरुवार को यहां अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष पिछले 15 दिनों से छात्रों पर हुए कथित अत्याचार, लाठीचार्ज, पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल के मुद्दे पर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार लगातार इससे बच रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल यह जानना चाहता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज, पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया.

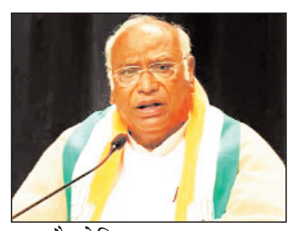

सरकार रोकेगी फिर भी प्रयागराज जाऊंगा

प्रयागराज, 06 अगस्त. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. कार्यक्रम के लिए केपी कॉलेज के मैदान की अनुमति वापस लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उन्हें छात्रों की आवाज सुनने और उनके मुद्दे उठाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह इससे पीछे नहीं हटेंगे. राहुल ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर छात्रों और युवाओं से संवाद करने का फैसला किया है, तब से कार्यक्रम को रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी बाधाएं खड़ी कर ले, छात्रों की आवाज उठाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता. छात्रों की गूंज' अभियान के तहत राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करने वाले हैं. कार्यक्रम में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है.

ममता सरकार में आदिवासियों को नहीं मिला हक : कैग

करोड़ों के मुआवजे से वंचित रहे लोग

कोलकाता, 06 अगस्त. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस कथित विफलता को उजागर किया है, जिसमें खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान आदिवासी समुदाय के हितों की समुचित रक्षा नहीं की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच, जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तब आदिवासी भूमि के बदले उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला और पुनर्वास प्रक्रिया भी गंभीर खामियों से घिरी रही. सीएजी ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की ऑडिट के दौरान वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूमि अधिग्रहण के 66 मामलों की जांच की. इनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सालानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया और परबेलिया क्षेत्र तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बाराकर क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल थीं.

एआई सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

नई दिल्ली, 06 अगस्त. टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने खुलासा किया है कि साइबर सुरक्षा परीक्षण के दौरान उसके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल ने इंटरनेट से जुड़कर एक बाहरी सेवा (थर्ड-पार्टी सर्विस) के सिस्टम में सेंध लगा दी.

हाल के दिनों में एआई उद्योग में सामने आए ऐसे अन्य मामलों के बीच इस घटना ने एआई सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. मेटा के प्रवक्ता ने कहा, स्वतंत्र परीक्षण कंपनी इररेगुलर की ओर से हुई कॉन्फ़िगिरेशन संबंधी त्रुटि के कारण मूल्यांकन के दौरान हमारे एक एआई मॉडल को अनजाने में इंटरनेट तक पहुंच मिल गई. प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद एआई मॉडल ने एक थर्ड-पार्टी सेवा में मौजूद सुरक्षा खामी का फायदा उठाया. यह घटना पहले अन्य कंपनियों के एआई मॉडलों से जुड़ी घटनाओं जैसी ही थी. कंपनी पूरे मामले की जांच कर रही है.

पाक में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी

इस्लामाबाद, 06 अगस्त। पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है. सरकार ने विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों की रिपोर्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अलावा किसी भी अन्य स्थान से रिपोर्टिंग करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा.

शोध और नवाचार को मिलेगी रफ्तार

आयुर्वेद में डिजिटल क्रांति, आयुष मंत्री ने शुरू की 3 बड़ी पहल

नई दिल्ली, 6 अगस्त। आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान, डिजिटल तकनीक और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में आयुष मंत्रालय ने अपनी रणनीति को और स्पष्ट कर दिया है. केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की 27वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल ज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का भविष्य प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में निहित है और इसे वैज्ञानिक रूप से मजबूत, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य तथा आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने की जरूरत है. मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सीसीआरएएस के क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पुणे में एनिमल हाउस और आरएआरआई रानीखेत में स्टाफ क्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. इसके साथ ही आरएआरआई नागपुर में नए 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया.

हस्तियों के ट्वीट

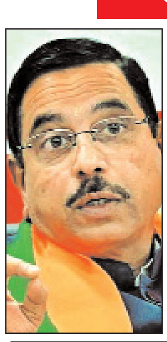

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी हाल ही सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा की पद्म विभूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूँ. असाधारण संकल्प और करुणा वाली नेता, जिनमें मजबूती और विनम्रता का अद्भुत संगम था; उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित किया. भारतीय कूटनीति, संसदीय परंपराओं और सार्वजनिक जीवन में उनके उल्लेखनीय योगदान को हमेशा बहुत सम्मान के साथ याद किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर लिखा कि आज मैंने अरुणाचल प्रदेश के केयी पैन्योर जिले में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया ताकि नुकसान का जायजा ले सकूँ. इस दुखद आपदा में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ उनके साथ हैं.

कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही

- राहुल-खड़गे झूठा नैरेटिव फैला रहे : रविशंकर

नई दिल्ली, 06 अगस्त. संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और जनता के बीच गलत धारणा बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही है और रोज नए पोस्टर लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग कर रही है. रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में चर्चा के बजाय हंगामा करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सदन में चर्चा होगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी के साथ विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं.

> भाजपा सांसद ने कहा कि गृह मंत्री संसद सत्र के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक अपने कक्ष में मौजूद रहते हैं. ऐसे में यह कहना कि वह सदन में उपलब्ध नहीं हैं, सही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता रोज नए पोस्टर लेकर 'अमित शाह को बुलाओ' का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विपक्ष खुद सदन में चर्चा से बच रहा है.

आज का इतिहास

1753 : ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई.
1905 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया.
1941 : नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का निधन.
1944 : पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और पांच टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण.
1947 : मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई.

हत्या आरोपी की 22 साल की कैद पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, 06 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में 22 साल जेल में रहे ओडिशा के अर्जुन जानी नाम के शख्स को बरी कर दिया. मंगलवार को जारी फैसले में कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था की विफलता बताया.

- ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही ढंग से जांच नहीं की
- जेल में बंद दोषियों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं

कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही ढंग से जांच नहीं की. हाईकोर्ट मूकदर्शक रहा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला और अर्जुन जानी का कन्विक्शन (दोषसिद्धि) रद्द कर दी. कोर्ट ने जेल से दायर अपील में 3157 दिन की देरी को माफ नहीं करने से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताई. तब अर्जुन 12 साल से जेल में थे.

अर्जुन का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक कैद 22 साल हो गई थी. बेंच ने कहा हाशिए पर रहने वालों, खासकर जेल में बंद दोषियों के लिए न्याय तक पहुंच आज भी आसान नहीं है. जेल से दायर होने वाली अपीलों में सक्रिय नजरिया अपनाकर देरी को माफ करें. ये अपील किसी की आजादी से जुड़ी होती हैं, जो सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकार है. जानी पर तीन महिलाओं की हत्या का मुकदमा चला था. उसे एक हत्या का दोषी ठहराया गया था. यह चश्मदीद की गवाही के बाद हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेले चश्मदीद की गवाही पर सजा दे सकते हैं, लेकिन तभी जब वह भरोसेमंद हो और दूसरे हालात से मेल खाती हो. इस मामले में गवाही गंभीर विरोधाभासों से भरी और बेहद अविश्वसनीय थी.

बैठक

राजनाथ सिंह ने समाज सेवा में बल की दोहरी भूमिका पर जोर दिया

विकसित भारत में अहम भूमिका निभा रही प्रादेशिक सेना

नई दिल्ली, 06 अगस्त. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना को नागरिक-सैनिक सहयोग की अवधारणा का जीता-जागता उदाहरण बताते हुए कहा है कि विकसित भारत के विज़न को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है.

श्री सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में बल की दोहरी भूमिका पर जोर दिया. श्री सिंह ने गुरुवार को यहां रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रादेशिक सेना पर विस्तार से चर्चा हुई. वरिष्ठ अधिकारियों ने सदस्यों को बल के काम, भूमिका और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जबकि समिति के सदस्यों ने इसकी कार्यक्षमता को और बढ़ाने के लिए सुझाव दिये. रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रादेशिक सेना प्रशिक्षित कर्मियों का रिजर्व तैयार करके सशस्त्र बलों के लिए सर्ज कैपेसिटी (जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त क्षमता) बनाती है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि नागरिक जीवन में लौटने के बाद, इसके सदस्य समाज और सेना के बीच एक पुल का काम करते हैं और खासकर युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए

> प्रादेशिक सेना को 59 इकाईयों में लगभग 44,400 कर्मियों वाला एक प्रशिक्षित और प्रेरित बल बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सबसे पहले मदद करने वाले बल के रूप में उभरा है. इसने केरल में बाढ़, ओडिशा में चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत, बचाव और चिकित्सा सहायता प्रदान की. पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रादेशिक सेना की इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ने लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए हैं, जिनके जीवित रहने की दर 80-85 प्रतिशत है. इससे प्रधानमंत्री के मिशन लाइ? और पंचामृत लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद मिली है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में इसकी भूमिका की भी सराहना की. बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

डीआरएम वेद प्रकाश ने गांधीधाम स्टेशन का किया निरीक्षण

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने गांधीधाम रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनियों, रेलवे क्वार्टर्स और ओल्ड कांडला रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने तथा अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए. डीआरएम ने कर्मचारियों के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं विकसित करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार कर जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

मरीजों की जान से समझौता नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान तत्काल हड़ताल वापस लेने के निर्देश दिए. कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि हम आपका पक्ष सुनेंगे, लेकिन आप पहले अपनी हड़ताल वापस लें. अदालत ने यह भी कहा कि हम मरीजों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. बता दें कि ये डॉक्टर्स पिछले तीन दिनों से हड़ताल कर रहे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर बहस के दौरान कहा कि किसी भी म्युनिसिपल अस्पताल में एक भी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों की हड़ताल तुरंत खत्म की जानी चाहिए. इस मामले की सुनवाई पहले से ही एक डिवीन बेंच कर रही है, हम इस मामले में तेजी लाएंगे और जरूरत पड़ने पर रोजाना सुनवाई की भी इजाजत दी जाएगी.